



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2001/चैत्र 21, 1923

No. 98]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2001/CHAITRA 21, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2001

सं. टीएएमपी/6/98-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार, कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) में कटेनर प्रहस्तन प्रभार अधिक होने के बारे में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं० टीएएमपी/6/98-सीपीटी

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी)

आवेदक

बनाम

कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी)

प्रत्यर्थी

आदेश

(28 मार्च 2001 को पारित)

यह मामला कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) में कटेनर प्रहस्तन प्रभार अधिक होने के बारे में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में है।

2 ईईपीसी ने अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं -

- (i) सीआई कास्टिंग और लौह एव इस्पात उत्पादों के निर्यात पर पहले ही अधिक समुद्री भाड़ा देना पड़ता है जो उनके मूल्य का लगभग 30% बैठता है।

- (ii) पत्तन प्रशुल्कों में बार-बार वृद्धि किए जाने से ये निर्यात कलकत्ता पत्तन न्यास के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्द्धी नहीं रहे हैं। अक्टूबर 1996 से कंटेनर युक्त कार्गो के प्रभारों में की गई वृद्धि से इजीनियरी निर्यातकों को कलकत्ता पत्तन न्यास का प्रयोग करने वाले पूर्वी क्षेत्र से बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
- (iii) कलकत्ता पत्तन में घाटभाड़ा प्रभार अधिक होने के साथ-साथ टर्मिनल प्रहस्तन प्रभार (टीएचसी) भी बहुत अधिक है।

3. इस अभ्यावेदन की एक प्रति सीपीटी को उसकी टिप्पणी के लिए भेजी गई। सीपीटी ने मार्च 1999 में सूचित किया कि पत्तन प्रभारों में संशोधन करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के संबंध में नियुक्त समिति द्वारा इस मामले पर पहले ही विचार किया जा चुका है और यह काम अप्रैल 1999 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

4. सीपीटी को कई अनुस्मारक जारी किए गए; और पत्तन यह पुष्टि करता रहा कि उसकी दरों के मान में सामान्य संशोधन करने के प्रस्ताव को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अंत में, सितंबर 2000 में सीपीटी ने प्रशुल्कों में सामान्य संशोधन बारे में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के साथ ही ईईपीसी के अभ्यावेदन पर भी विचार किया गया और कोलकाता में 24 नवंबर 2000 को हुई संयुक्त सुनवाई में उस पर चर्चा की गई।

5.1 कलकत्ता डॉक सिस्टम (सीडीएस) में मौजूदा कंटेनर प्रहस्तन प्रभार अक्टूबर 1996 से प्रभावी हैं, और इतनी पूर्ववर्ती तारीख से पूर्व प्रभावी समीक्षा एवं संशोधन करना संभव नहीं है। सीपीटी द्वारा प्रशुल्कों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत सीडीएस में कंटेनर प्रहस्तन कार्य के लागत विवरण से राजस्व के काफी अधिक होने की स्थिति का पता चलता है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह कार्य सीडीएस के कुछ अन्य कार्यों को प्रति सहायता दे रहा है। प्रति-सहायता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार किया जाना है। प्रथम दृष्टि में प्रति सहायता को एक बार में ही इस प्रकार समाप्त किए जाने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिसका कम मूल्य वाली कमजोर वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा। तथापि प्राधिकरण ने पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि प्रति सहायता को कम से कम वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जाए। इस दृष्टिकोण के अनुसार भले ही सीपीटी ने प्रशुल्कों में सामान्य संशोधन के अपने प्रस्ताव में कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों में वृद्धि का प्रस्ताव किया था, परंतु यह वृद्धि मंजूर नहीं की गई।

5.2 हालांकि कंटेनर प्रहस्तन कार्य के लिए प्रशुल्कों में किसी वृद्धि का अनुमोदन नहीं किया गया है तथापि सीपीटी ने सीआई माल सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए बॉक्स दरें कम करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कमी लगभग 900/- रु० प्रति टीईयू है। इसके अलावा सीपीटी ने एक वित्त वर्ष में 100 टीईयू से अधिक प्रहस्तित अतिरिक्त टीईयू पर दरों में 10% की छूट देने का भी प्रस्ताव किया है।

5.3 इसी प्रकार, पत्तन ने ब्रेक बल्क में प्रहस्तित लौह एवं इस्पात तथा सीआई माल सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो के लिए मात्रा छूट देने का भी प्रस्ताव किया है। सीडीएस में भारी सामान पर पृथक घाटभाड़े की वसूली को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। उत्थापन प्रभार भी केवल तभी वसूल करने का प्रस्ताव किया गया है जब यदि पत्तन के उपस्कर का प्रयोग किया जाए; और सीडीएस में सीमा भी बढ़ाकर पाँच टन कर दी गई है। प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, जो सभी पत्तनों का सामान्य रूप से स्वीकार्य होगा, एचडीसी में भारी सामान की सीमा को बढ़ाकर 20 टन कर दिया गया है; और लौह एवं इस्पात के लिए भारी सामान प्रभारों को कम कर दिया गया है। भारी सामान प्रभारों में कमी करने के साथ-साथ भारी सामान को यगीकृत करने के लिए सीमा को बढ़ाने से लौह एवं इस्पात के परेषणों को काफी राहत मिलेगी।

5.4 सीपीटी के उपर्युक्त प्रस्तावों को आज प्राधिकरण द्वारा सीपीटी की दरों के मान में संशोधन करने से संबंधित मामले पर निर्णय करते समय पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। संशोधित दरों के मान को क्रियान्वित करने से ईईपीसी को कम से कम आंशिक तौर पर तो अपेक्षित राहत अवश्य मिलेगी।

6. ईईपीसी द्वारा टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों (टीएचसी) के संबंध में उठाए गए मुद्दे संगत हैं। कुछ शर्तों को पूरा करने पर टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों का विनियमन प्राधिकरण के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। हाल में मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ने टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों को विनियमित करने का प्रस्ताव किया है और प्राधिकरण से टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सेवा घटकों के लिए उच्चतम दरे निर्धारित करने का अनुरोध किया है; और पत्तन इन दरों को सेवा प्रदाताओं को पत्तन सीमाओं के भीतर ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करते समय लागू करेगा। हमने एमबीपीटी के मॉडल को सभी पत्तन न्यासों में परिचालित किया है और उनसे तदनुसार अपने-अपने पत्तनों में टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों के विनियमन के संबंध में प्रस्ताव तैयार करते समय इस मॉडल को ध्यान में रखने का अनुरोध किया है। सीपीटी को यह परामर्श दिए जाने के बाद से लगभग एक वर्ष बीत चुका है, परंतु सीपीटी में टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों के विनियमन के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त सुनवाई में, प्राधिकरण के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से सीपीटी के अध्यक्ष को इस स्थिति से अवगत कराया था। सीपीटी से आग्रह किया जाता है कि वह इस मामले की तत्काल जाँच करके अपना प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ भेजे।

7. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए तर्कों तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण ईईपीसी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अनावश्यक मानता है क्योंकि उसके द्वारा उठाए गए लगभग सभी मुद्दों पर सीपीटी के प्रशुत्कों के सामान्य संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा चुका है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2001/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2001

No. TAMP/6/98-CPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by the Engineering Export Promotion Council (EEPC) about high container handling charges at the Calcutta Port Trust (CPT), as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/6/98-CPT

Engineering Export Promotion Council (EEPC) ... Applicant

Vs.

The Calcutta Port Trust ... Respondent

ORDER

(Passed on this day of 28th March 2001)

This case relates to a representation received from the Engineering Export Promotion Council (EEPC) about high container handling charges at the Calcutta Port Trust (CPT).

2. In its representation, the EEPC has made the following points:

(i). The export of CI castings and iron and steel products already pay a high sea freight,

- (ii). Frequent hike in port tariffs has rendered these exports uncompetitive in international trade through Calcutta Port Trust. The upward revision of charges for containerised cargo effected from Oct. 1996 is causing great hardships to the engineering exporters from the eastern region using Calcutta Port Trust.
 - (iii). Apart from a high wharfage charge, terminal handling charges (THC) at the Calcutta Port are very high.
3. A copy of this representation was forwarded to the CPT for its comments. The CPT, in March 1999, informed that the matter had already been taken up by a committee appointed in connection with revision and rationalisation of port charges; and, the work would be completed by the end of April 1999.
4. Several reminders were issued to the CPT; and, the Port continued to affirm that its proposal for general revision of its Scale of Rates would be finalised shortly. Finally, the CPT submitted its proposal for general revision of tariffs in September 2000. The representation of the EEPC has also been considered alongwith the general revision proposal and taken up in a joint hearing held on 24 Nov. 2000 in Kolkata.
- 5.1. The existing container handling charges at the Calcutta Dock System (CDS) have been in force since October 1996; and, a retrospective review and revision is not possible at such a distant date. The cost statement for container handling activity at the CDS, furnished by the CPT along with its proposal for general revision of tariffs, shows a revenue surplus position. This clearly indicates that this activity is cross-subsidising some other activities of the CDS. A final view on complete elimination of cross-subsidisation is yet to be taken by this Authority. Prima facie, such an elimination at one go may have serious repercussions on low value weak commodities. Nevertheless, the Authority has already decided that cross-subsidisation must at least be contained at the present level. In line with this approach, even though the CPT has proposed an increase in container handling charges in its general revision of tariffs proposal, such an increase has not been allowed.
- 5.2. Although no increase in the tariffs for the container handling activity is approved, the CPT has proposed to reduce the box rates for export of various commodities including CI goods. The reduction proposed is about Rs. 900/- per TEU. In addition, the CPT has also proposed to allow a rebate of 10% on the rates on additional TEUs handled in excess of 1200 TEUs in a financial year.
- 5.3. Similarly, the Port has also proposed to introduce volume discounts for various types of cargo including iron and steel and CI goods handled as breakbulk. Levy of a separate wharfage on heavy lifts at the CDS has been proposed to be abolished. The lifting charges have also been proposed to be levied only if port equipment are used; and, the limit has been enhanced to five tones at CDS. At the HDC, the heavy lift limit has been increased to 20 tonnes, in terms of the Authority's Order for common adoption by all ports; and, the heavy lift charges for iron and steel have been reduced. The enhancement of the limit for classifying heavy lift alongwith the reduction in heavy lift charges will provide substantial relief to iron and steel consignments.

5.4. The proposals of the CPT mentioned above have already been approved by this Authority earlier today while deciding the case relating to revision of the CPT Scale of Rates. When implemented, the revised Scale of Rates will provide, at least partially, the relief the EEPC is looking for.

6. The issues raised by the EEPC about Terminal Handling Charges (THC) are relevant. Subject to fulfilment of certain conditions, regulation of the THC comes under the ambit of this Authority's jurisdiction. Recently, the MBPT has proposed to regulate the THC and requested this Authority to fix the ceiling rates for various service components covered by the THC; and, the Port will enforce such rates while authorising the service providers to render such services within the port limits. We have circulated the MBPT model to all the port trusts and requested them to consider formulating their proposals for regulation of THC in their ports accordingly. Nearly one year has elapsed since such advice was given to the CPT; but, no proposal for regulation of THC at the CPT has been received. At the joint hearing, the Chairman of the Authority had personally drawn this position to the notice of the Chairman of the CPT. The CPT is urged to look into this issue immediately and forward its proposal to this Authority for consideration.

7. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority disposes of the representation of the EEPC as superfluous since most of the issues raised by it have been dealt with in the context of the general revision of tariffs of the CPT.

S. SATHYAM, Chairman
[Advt III/IV/143/2001/Exty.]

